संगठनात्मक संरचना और कार्य

01
अध्याय

संगठनात्मक संरचना और कार्य

परिचय

कोयला मंत्रालय के पास कोयला और लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों और रणनीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने और सभी संबंधित मामलों को तय करने की समग्र जिम्मेदारी है। इन प्रमुख कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), जो तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, के माध्यम से किया जाता है, जिसकी इक्विटी पूंजी 51:49 के अनुपात में है।

विजन

कोयला मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पर्यावरण अनुकूल और सतत तरीके से पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इसके दृष्टिकोण और अत्याधुनिक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देने के साथ अन्वेषण में वृद्धि करके और कोयला निष्कर्षण से आवश्यक अवसंरचना के विकास द्वारा सरकारी कंपनियों के साथ–साथ कैप्टिव खनन रूट मार्ग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के समग्र मिशन से जुड़े हैं।

उद्देश्य

i. कोयला उत्पादन और आफटेक, ओबीआर हटाने, लिग्नाइट उत्पादन और लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना।

ii. कोयले और धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवसंरचना का विकास।

iii. पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

iv. अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहल।

v. संसाधन आधार बढ़ाने के लिए अन्वेषण को बढ़ाना।

vi. ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता।

vii. अंतर–मंत्रालयी मुद्दों का त्वरित और संयुक्त समाधान।

viii. कोल इंडिया की दक्षता में सुधार।

ix. निजी निवेश को आकर्षित करना।

x. पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है।

कोयला मंत्रालय (कोयला मंत्रालय) के कार्य

कोयला मंत्रालय भारत में कोयला और लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास और दोहन से संबंधित है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत समय–समय पर यथा संशोधित कोयला मंत्रालय को आबंटित विषय (अधीनस्थ या अपने विषयों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य संगठनों सहित) निम्नानुसार हैं: –

i. भारत में कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों की अन्वेषण और विकास।

ii. कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निधारण से संबंधित सभी मामले।

iii. उन कोयला वाशरियों के अलावा अन्य कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है।

iv. कोयले का निम्न तापमान वाला कार्बनीकरण और कोयले से सिंथेटिक तेल का उत्पादन।

v. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

vi. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

vii. कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

viii. कोयला खान कल्याण संगठन।

ix. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन

x. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

xi. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 का प्रशासन (1973 का 26)

xii. कोयला खान प्रशासन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015

xiii. खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।

xiv. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

xv. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, अब तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंधकोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

1. संगठन संरचना

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिसे–

(क) 2 (दो) अपर सचिव (संयुक्त सचिव के एक पद को अपर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है)

(ख) एक वित्तीय सलाहकार सहित 3 (तीन) संयुक्त सचिव,

(ग) 1 (एक) उप महानिदेशक,

(घ) 1 (एक) आर्थिक सलाहकार

(ड.) 2 (दो) निदेशक (तकनीकी);

(च) 11 (ग्यारह) निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक;

(छ) 14 (चौदह) अवर सचिव/उप निदेशक (संख्याकिकी)उप निदेशक (ईसीओ),

(ज) 26 अनुभाग अधिकारी/स.नि. (रा.भा.)

(छ) लेखा नियंत्रक;

(झ) एक लेखा उप नियंत्रक; और

(प) 2 वरिष्ठ लेखा अधिकारी।

2. अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन में हैं ––

(i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय – एक अधीनस्थ कार्यालय;

(ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्त निकाय।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

i. कोल इंडिया लिमिटेड

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल))

iii. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

3. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और 214333 की जनशक्ति (1 जनवरी, 2026 तक) के साथ सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से एक है।सीआईएल भारत के आठ (8) राज्यों में फैले 85 खनन क्षेत्रों के माध्यम से कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 310 चालू खदानें (1 अप्रैल, 2025 तक) हैं, जिनमें से 129 भूमिगत, 168 ओपनकास्ट और 13 मिश्रित खदानें हैं।

सीआईएल की ग्यारह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।

i. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल),

ii. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल),

iii. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल),

iv. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल),

v. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल),

vi. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL),

vii. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल),

viii. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल),

ix. सीआईएल नवीकरणीय उर्जा लिमिटेड

x. सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड

xi. कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) – विदेशी सहायक कंपनी

इसके अलावा, सीआईएल की तीन सहायक कंपनियां हैं जो पूर्ण स्वामित्व में नहीं हैं।

i. भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (51 प्रतिशत होल्डिंग),

ii. कोल गैस इंडिया लिमिटेड (51% होल्डिंग),

iii. सीआईएल राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड (74% होल्डिंग)।

असम में खानों यानी पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स का प्रबंधन सीधे सीआईएल द्वारा किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की चार (4) सहायक कंपनियां हैं, एसईसीएल की दो (2) सहायक कंपनियां हैं और सीसीएल की एक (1) सहायक कंपनियां हैं।

सीआईएल की निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियां भी हैं

i. सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल के बीच हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) जिसमें सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में उर्वरक (अमोनिया, यूरिया और नीम लेपित यूरिया) के निर्माण के लिए सीआईएल की 31.3.25 तक 29.67% हिस्सेदारी है।

ii. आरसीएफ, सीआईएल, गेल और एफसीआईएल के बीच तलचर फटिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) जिसमें 31–3–25 की स्थिति के अनुसार तालचेर, ओडिशा में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के साथ उर्वरक परियोजनाओं और रासायनिक विनिर्माण (यूरिया) परिसर के लिए सीआईएल की हिस्सेदारी 31.85% है

iii. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड– सीआईएल और एनटीपीसी के बीच जिसमें सीआईएल की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 50% हिस्सेदारी है।

iv. कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड– सीआईएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच, जिसमें सीआईएल की विद्युत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

v. इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड।

ताप विद्युत परियोजनाएं

ताप विद्युत क्षेत्र में अपने प्रवेश के हिस्से के रूप में, सीआईएल ने चंद्रपुरा, झारखंड में 2x800 मेगावाट की अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के ब्राउनफील्ड विकास के लिए 50:50 इक्विटी–शेयरिंग के आधार पर डीवीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयंत्र को वित्त वर्ष 31–32 तक चालू किया जाना है। दीपम की मंजूरी मिल गई है

नवीकरणीय ऊर्जा

- शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में सीआईएल के अभियान में सौर ऊर्जा उत्पादन प्रमुखता से सूचीबद्ध है। वित्त वर्ष 24–25 तक कुल 209.08 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई थी। सीआईएल ने दिसंबर, 25 तक अपनी सहायक कंपनियों में 23.42 मेगावाट की एक और सौर क्षमता जोड़ी है और 638.5 मेगावाट सौर क्षमता स्थापना चरण में है।
- 300 मेगावाट और 100 मेगावाट (गुजरात में) की मेगा सौर परियोजनाएं प्रदान की गई हैं और 875 मेगावाट – राजस्थान निविदा चरण में है। सौर ऊर्जा का उत्पादन वित्त वर्ष 25–26 में 25 नवंबर, 25 तक 150 मिलियन यूनिट है।
- सीआईएल ने आरआरवीयूएनएल (सीआईएल राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड) के साथ अपने निगमित संयुक्त उद्यम के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लगभग 2,100 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें पुगल में 875 मेगावाट सौर संयंत्र शामिल है जिसके लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है।

- सीआईएल ने यूपी राज्य में एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 500 मेगावाट आरई परियोजनाओं के सहयोगात्मक विकास के लिए यूपीआरवीयूएनएल (आरआरवीयूएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सीआईएल कैप्टिव मोड के तहत 4500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास की सक्रिय रूप से संभावनाएं तलाश रहा है, जिसमें 3000 मेगावाट सौर और 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। उत्पादित बिजली की आपूर्ति कैप्टिव उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से की जाएगी।

4. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम है, जिसमें क्रमशः तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारतीय कोयला उत्पादन का लगभग 7.5 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है।

एससीसीएल का पंजीकृत कार्यालय कोठागुडेम, भद्राद्री जिला, तेलंगाना में है। कंपनी वर्तमान में तेलंगाना के छह जिलों में 17 ओपनकास्ट (ओसी) खानों और 21 भूमिगत (यूजी) खानों का संचालन करती है, जिसमें 40,186 कर्मचारी (31.12.2025 तक) कार्यरत हैं। एक नई खदान, वीके ओपनकास्ट (5.3 एमटीपीए रेटेड क्षमता), ने अक्टूबर 2025 में ओवरबर्डन हटाना शुरू किया। जनवरी 2026 से कोयले का उत्पादन होने की उम्मीद है।

ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त 2015 में एससीसीएल को आवंटित नैनी कोयला ब्लॉक (10 एमटीपीए) ने जुलाई 2025 में कोयला उत्पादन शुरू किया, जिससे दिसंबर 2025 तक लगभग 80,000 टन का उत्पादन हुआ। वर्तमान में कोयला परिवहन की व्यवस्था चल रही है।

कोयला खनन के अलावा, एससीसीएल ने थर्मल पावर उत्पादन, सौर ऊर्जा, कैप्टिव उपयोग के लिए विस्फोटक निर्माण और ओवरबर्डन से संसाधित रेत उत्पादन में विविधता लाई है।

थर्मल पावर: 2x600 मेगावाट का सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) 2016 से मंचेरियल जिले में काम कर रहा है। उसी साइट पर एक नया 1x800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (चरण– II) निर्माणाधीन है और अप्रैल 2029 तक चालू होने के लिए निर्धारित है।

सौर ऊर्जा: एससीसीएल ने 504.5 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की योजना बनाई है। 1 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 245.50 मेगावाट पहले ही चालू हो चुकी है और 362 एमयू का उत्पादन किया जा चुका है । कुल शेष क्षमता में से 227 मेगावाट निर्माणाधीन है और 32 मेगावाट निविदा चरण में है। निर्माणाधीन 227 मेगावाट में से 67.5 मेगावाट के मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

रूफ–टॉप सौर परियोजनाएं: एससीसीएल प्रतिष्ठानों में कुल 32.75 मेगावाट प्रस्तावित हैं और मई 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। अब तक, 0.15 मेगावाट चालू होने की उम्मीद है और मार्च–2026 तक 21.5 मेगावाट और शेष 11.10 मेगावाट मई 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण खनिज:

एससीसीएल ने अन्वेषण लाइसेंस के लिए खान मंत्रालय के एनआईटी में भाग लिया और देवदुर्गा में सोने और तांबे की खोज ब्लॉक को सफलतापूर्वक सुरक्षित किया। डीएमजी, कर्नाटक द्वारा 28.10.2025 को आशय पत्र जारी किया गया था। स्थानीय वन अधिकारियों से वन मंजूरी का अनुरोध किया गया है, और अनुमति मिलने के बाद अन्वेषण शुरू हो जाएगा।

अन्य रणनीतिक पहल: एससीसीएल कई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें 500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट, 800 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, सीओ$_2$–टू–मेथनॉल उत्पादन सुविधा, कोयला–से–अमोनियम नाइट्रेट परियोजना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) एससीसीएल के प्रचालन क्षेत्रों के भीतर मिट्टी, शेल, ओवरबर्डन और फ्लाई ऐश से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निष्कर्षण शामिल है।

5. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एक "नवरत्न" कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है और कॉर्पोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है, जो ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों में कई परियोजनाओं को तैयार किया है और अपने पंखों का

विस्तार किया है, जिसमें पैन इंडिया फुटप्रिंट के साथ देश भर में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है। एनएलसीआईएल लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करने वाली और थर्मल पावर और हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाली एक ऊर्जा प्रमुख कंपनी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रचालन का विवरण नीचे दिया गया है:–

एनएलसीआईएल की संरचना

लिग्नाइट खानें:

- नेवेली, तमिलनाडु में 28.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की कुल क्षमता की तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खान और बरसिंगसर, राजस्थान में 2.10 एमटीपीए क्षमता की एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान। लिग्नाइट के क्षेत्र में वर्तमान स्थापित क्षमता 30.1 एमटीपीए है।

कोयला खानें:

- 20.00 एमटीपीए तालाबीरा II और III ओसी माइन ऑपरेशन 11 दिसंबर 2019 को एमडीओ मोड के तहत शुरू हुआ। तालाबीरा खानों से कोयले का उत्पादन 26 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था।

लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन:

- नेवेली, तमिलनाडु में 3390 मेगावाट (मेगावाट) की कुल संस्थापित क्षमता वाले चार लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशन और 250 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ बरसिंगसर, राजस्थान में एक थर्मल पावर स्टेशन। कुल स्थापित लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 3640 मेगावाट है।

नवीकरणीय ऊर्जा:

- एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 51 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु के नेवेली में 151.06 मेगावाट, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में "1,209 मेगावाट" और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में "20 मेगावाट" सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता के साथ सौर संयंत्र भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, एनएलसीआईएल ने नेवेली में खनन क्षेत्र में 8.8 मेगावाट की सौर परियोजना और राजस्थान के बरसिंगसर में 158.83 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। इसके साथ ही एनएलसीआईएल की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 1,598.69 मेगावाट हो गई है।

कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन:

- एनएलसीआईएल वर्तमान में तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट और घाटमपुर, उत्तर प्रदेश में

2ग660 मेगावाट के साथ 2,320 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल क्षमता का संचालन कर रहा है।

- एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) के माध्यम से तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 500 मेगावाट क्षमता (1000 मेगावाट) की दो यूनिटों के साथ एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र प्रचालन में है, जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड और टीएएनजीईडीसीओ (89:11 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी) है।
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपीआरवीयूएनएल (51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी) के बीच एक संयुक्त उद्यम, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जिसमें 660 मेगावाट प्रत्येक की तीन इकाइयां (कुल 1,980 मेगावाट) हैं। इनमें से दो इकाइयां (1,320 मेगावाट) चालू हो चुकी हैं और प्रचालन में हैं।
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 7,558.69 मेगावाट है।
- तमिलनाडु में नेवेली में पांच लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन और तीन खानों के साथ–साथ बरसिंगसर, राजस्थान में लिग्नाइट खान और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) से प्रमाणित हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड का विकास निरंतर है और भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका योगदान महत्वपूर्ण है.

विकासाधीन परियोजनाएं:

- एनएलसीआईएल और यूपीआरवीयूएनएल के बीच एक संयुक्त उद्यम नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) 21,780.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से घाटमपुर उत्तर प्रदेश में 3ग660 मेगावाट की घाटमपुर कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (जीटीपीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। यूनिट–1 को 12.12.2024 को और यूनिट–2 को 09.12.2025 को चालू किया गया था। यूनिट–3 (660 मेगावाट) के फरवरी–2026 में चालू होने की उम्मीद है।
- ओडिशा में 2400 मेगावाट की पिटहेड कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (एनटीटीपीपी) को एनएलसीआईएल द्वारा ओडिशा में एक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके वित्त वर्ष 2029–30 में चालू होने की उम्मीद है, जिसमें भूमि अधिग्रहण गतिविधियां चल रही हैं और मुख्य संयंत्र क्षेत्र की भूमि पर कब्जा लगभग पूरा हो गया है। लगभग 52000 वर्ग मीटर क्षेत्र को समतलित करने का काम पूरा हो चुका है और परीक्षण पाइलिंग का काम शुरू हो गया है। ऐश डाइक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त भूमि और भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है,
- सरकारी भूमि का अग्रिम कब्जा पहले ही पूरा हो चुका है। मेसर्स बीएचईएल को 12.01.2024 को ईपीसी अनुबंध दिया गया। मैसर्स बीएचईएल को 27.11.2024 को आगे बढ़ने के लिए नोटिस (एनटीपी) जारी किया गया।
- पछवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक (पीएससीबी) (9 एमटीपीए), दुमका, झारखंडः 23.09.2024 को ईसी ने मंजूरी दी 455.1108 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए 25.07.2025 को एफसी (चरण–II) प्रदान किया गया। सीसीओ, एमओसी द्वारा 22.10.2025 को खान खोलने की अनुमति दी गई और 19.12.2025 को खनन कार्य शुरू हुआ।
- एसईसीआई से 150 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं:

  50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए – माननीय प्रधानमंत्री ने 20.09.2025 को आधारशिला रखी। 8 पवन चक्कियों और 12 के लिए नींव का निर्माण पूरा हो गया है। वर्तमान में निर्माण और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं।

  100 मेगावाट सौर पीपी के लिए, मैसर्स एनर्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एलओए जारी किया गया है। 460 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और कानूनी जांच के लिए दस्तावेज जमा किए गए हैं। 433 एकड़ के लिए भूमि के मालिकों को मंजूरी दी गई और 97.67 एकड़ को कवर करने वाले पट्टे के समझौतों पर भूस्वामियों के साथ हस्ताक्षर किए

गए। ठेकेदार से शेष भूमि विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

- इरेडा की 510 मेगावाट सौर पीवी बिजली परियोजना:

  नेवेली में स्मार्ट सिटी रूपांतरण के तहत 10 मेगावाट की सौर परियोजना 30.10.2023 को चालू की गई।

  300 मेगावाट की सौर परियोजना, राजस्थान: अब तक 158.83 मेगावाट चालू हो चुकी है। शेष क्षमता के लिए निर्माण/निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। प्रत्याशित सीओडी–दिसंबर, 2025 में है।

  200 मेगावाट की सौर परियोजना, गुजरात: पीवी मॉड्यूल और बीओएस की खरीद से संबंधित गतिविधियां प्रगति पर हैं। 800 एकड़ की कुल भूमि आवश्यकता में से, ठेकेदार ने 445.83 एकड़ के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए, और 169.479 एकड़ के लिए पट्टा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 27.08.2025 को स्थल पर ग्राउंडब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया और काम शुरू हो गया।

- 600 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना: एनएलसीआईएल ने गुजरात के खावड़ा सौर पार्क में 600 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए ग्रीन शू योजना के तहत गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा आयोजित नीलामी में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की बोली जीती है।

  बीओएस वर्क्स के लिए, बोंडाडा इंजीनियरिंग को 12.06.2024 को एलओए जारी किया गया था। मॉड्यूल आपूर्ति के लिए, मैसर्स विक्रम सोलर लिमिटेड को पहली लॉट (393.9 मेगावाट) के लिए एलओए जारी किया गया था। दूसरे लॉट के लिए, मेसर्स कोसोल को 07.12.2024 को एलओए जारी किया गया।

  स्थलाकृति/रूपरेखा, जल विज्ञान सर्वेक्षण और भू–तकनीकी जांच कार्य पूरे हो गए हैं। मॉड्यूल की प्राप्ति शुरू हो गई है और पाइलिंग का काम प्रगति पर है।

- राजस्थान क्षेत्र में 810 मेगावाट सौर: एनएलसीआईएल ने आरआरवीयूएनएल द्वारा जारी निविदा में प्रतिस्पर्धी बोली के तहत परियोजना हासिल की, जिसकी योजना पुगल सोलर पार्क, बीकानेर, राजस्थान में बनाई गई थी। पीपीए पर 06.05.2025 को आरआरवीयूएनएल के साथ हस्ताक्षर किए गए । आरआरवीयूएनएल और एनआईआरएल के बीच 26.09.2025 को कार्यान्वयन और सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पीवी मॉड्यूल और बीओएस पैकेज दोनों के लिए निविदाएं जारी की गईं। 17.12.2025 को बीओएस पैकेज के विकास के लिए मैसर्स बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड को एलओए रखा गया।

- खनन क्षेत्र में 50 मेगावाट सौर: मॉड्यूल खरीद के लिए क्रमशः 25.03.2024 और 26.02.2024 को बीओएस पैकेज जारी किया गया। 27.09.2025 को 8.8 मेगावाट सिंक्रनाइज़ और माइन सबस्टेशन से जुड़ा हुआ। शेष क्षमता दिसंबर–25 तक पूरी होने की उम्मीद है।

- रूफटॉप सोलर: एनएलसीआईएल ने नेवेली में 1.06 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया है और अब एनएलसीआईएल और उसके संयुक्त उपक्रमों में कार्यालय भवनों में 4 मेगावाट की रूफटॉप सौर परियोजनाओं को लागू कर रहा है। 02.06.2025 को मैसर्स सन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एलओए जारी किया गया था, और एमएमएस और पीवी मॉड्यूल की प्राप्ति के साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के दिसंबर 25 तक पूरा होने की उम्मीद है।

- लिग्नाइट से मेथनॉल: एक विविधीकरण पहल के रूप में, एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु के नेवेली में 2.28 एमटीपीए की लिग्नाइट फीड दर के साथ 1200 टीपीडी मेथनॉल की क्षमता के साथ लिग्नाइट से मेथनॉल गैसीकरण परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। संशोधित डीएफआर के अनुसार, अनुमानित परियोजना लागत 16,220 करोड़ रुपये है जो प्रारंभिक अनुमानित परियोजना लागत का चार गुना है और आईआरआर मूल्य नकारात्मक हैं। संशोधित डीएफआर की समीक्षा एनएलसीआईएल द्वारा की जा रही है।

- एम–सैंड पर ओवरबर्डन: हरित पहल के हिस्से के रूप में और प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग में 'वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा' को अधिकतम करने और पर्यावरण और नदी इको–सिस्टम पर प्रभाव को कम करने के लिए

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दी जा रही स्थायी प्रथाओं के अनुरूप, एनएलसीआईएल ने अपने तीनों खानों के ओवरबर्डन डंप से निर्माण ग्रेड रेत निकालने का प्रस्ताव किया है।

एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु के नेवेली के खान–आईए में 0.42 एमटीपीए क्षमता का संयंत्र स्थापित किया। तमिलनाडु के नेवेली स्थित खान–ए में 1 एमटीपीए क्षमता का एक अन्य ओबी से एम–सैंड संयंत्र प्रगति पर है।

- महत्वपूर्ण खनिज: ट्रेंच–V में, एनएलसीआईएल रायपुर फॉस्फोराइट और चूना पत्थर ब्लॉक (राजस्व साझाकरण - 8.60%) और सेमहार्डीह फॉस्फोराइट और चूना पत्थर ब्लॉक (राजस्व साझाकरण - 11.05%) के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में उभरा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आशय पत्र। समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए, एनएलसीआईएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली "पूर्वेक्षण योजना" और इसकी तैयारी की जा रही है।

पाइपलाइन/सूत्रीकरण के तहत परियोजनाएं:

- टीपीएस–II दूसरा विस्तार (2ग500 मेगावाट), 1000 मेगावाट क्षमता का एक लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जिसमें 500 मेगावाट क्षमता की दो यूनिटों के साथ मुदानाई गांव (नेयवेली के निकट), कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो नेवेली की लिग्नाइट खानों से जुड़ा हुआ है। 2x500 मेगावाट के संशोधित विन्यास के लिए, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संशोधित विद्युत आबंटन और ईसी के लिए संशोधन प्राप्त करने (2'660 मेगावाट विन्यास के लिए पहले से ही प्राप्त) प्रगति पर है। परियोजना के लिए भूमि पहले से ही कब्जे में है। परियोजना की पहली इकाई को ठेका दिए जाने की तारीख से 50 महीने में और दूसरी इकाई को 6 महीने की फेज शिफ्ट के साथ चालू किया जाना है। एकल पैकेज ईपीसी अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदा 10.12.2025 को जारी की गई थी।

- माइन III: 11.5 एमटीपीए की पीक रेटेड क्षमता वाली परियोजना को 3893 हेक्टेयर के परियोजना क्षेत्र को शामिल करते हुए टीपीएस II दूसरे विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू करने का प्रस्ताव है। ब्लॉक में 426.02 मीट्रिक टन का खनन योग्य भंडार है। तमिलनाडु सरकार से भूमि अधिग्रहण की मंजूरी प्रारंभिक चरण में है।

- उत्तरी धाडू (पश्चिमी भाग) (3 एमटीपीए): एनएलसीआईएल झारखंड के लातेहार जिले में उत्तरी धाडू (पश्चिमी भाग) के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। 03.11.2025 को एमडीओ मोड के माध्यम से उत्तरी धाडू के विकास और संचालन के लिए एलओए जारी किया गया। झारखंड सरकार द्वारा ब्लॉक सीमा से परे अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 04.11.2025 को एनओसी जारी की गई। खनन योजना और खानबंद करने की योजना के लिए अनुमोदन 20.11.2025 को प्राप्त हुआ।

- मछकाटा कोयला ओसीपी (30 एमटीपीए): एनएलसीआईएल ओडिशा के अंगुल जिले में मछकाटा (संशोधित) कोयला खान(30 एमटीपीए) के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। एमओसी द्वारा 05.09.2024 को जारी निहित आदेश भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को 26.03.2025 को मंजूरी दी गई।

- न्यू पात्रापाड़ा दक्षिण (12 एमटीपीए): एनएलसीआईएल ओडिशा के अंगुल जिले में न्यू पात्रापारा दक्षिण (12 एमटीपीए) के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। एमओसी द्वारा 04.02.2025 को जारी निहित आदेश भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को 07.08.2025 को मंजूरी दी गई।

6. कोयला नियंत्रक का संगठन:

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर और कोठागुडेम में हैं। दिल्ली और कोलकाता के अलावा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व ओएसडी द्वारा किया जाता है, जिन्हें अन्य तकनीकी अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

संगठन का प्रमुख कोयला नियंत्रक होता है, प्रशासनिक को निदेशक (आईएसएस), एक उप निदेशक (आईएसएस) और दो उप सहायक कोयला नियंत्रक और अन्य अधिकारी द्वारा समर्थित किया जाता है।

सीसीओ दिल्ली, सीसीओ कोलकाता और धनबाद कार्यालय में 31.12.2025 तक वर्तमान कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

31.12.2025 तक जनशक्ति की स्थिति

जन शक्ति	समूह क	समूह ख		समूह ग	कुल
	राजपत्रित	राजपत्रित	गैर राजपत्रित	गैर राजपत्रित	
मंजूर की गई	43	31		56	130
वर्तमान में	05	17		28	50

कोयला नियंत्रक संगठन का सुदृढ़ीकरण:

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सीसीओ के कैडर पुनर्गठन के तहत सीसीओ के 130 पदों को मंजूरी दी है। नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने और रिक्त स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया एमओसी/सीसीओ के रूप में प्रक्रियाधीन है।

कार्य:

कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित क़ानूनों से प्राप्त विभिन्न वैधानिक कार्यों का निर्वहन करता है:

(i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (2025 में संशोधित)।

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)

(iii) कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)

(iv) सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करें

कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है:

(क) कोयले के वर्ग, ग्रेड अथवा आकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोलियरियों का निरीक्षण।

(ख) कोलियरी में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेडों की घोषणा और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए निर्देश जारी करना।

(ग) कोयले के ग्रेड की घोषणा से उत्पन्न उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

(ङ) ग्रेडों और आकारों के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मालडिपों/ट्रकों में कोयले के ग्रेड के अनुरक्षण, लदान के संबंध में गुणवत्ता निगरानी।

(च) कोयला खान, सीम या सीम के किसी खंड को खोलने/पुन खोलने की अनुमति प्रदान करना अथवा किसी खान को उप–विभाजित करना।

(छ) खनन योजना और खान बंद करने की योजना का अनुमोदन

(ज) वाशरी का कार्यान्वयन नीति को अस्वीकार करता है

(प) स्टार रेटिंग नीति के अंतर्गत खानों की समीक्षा/मूल्यांकन

(ञ) एस्क्रो खातों से प्रगतिशील/अंतिम रूप से खान बंद करने की गतिविधियों के लिए निधियों की प्रतिपूर्ति

(ट) कोयला खान संरक्षण और विकास खाते से ऋण की रकम का संवितरण:

(एल) कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयलाधारी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आपत्तियों को सुनना और केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

(ड) नीलामी के लिए प्रस्तावित कोयला ब्लॉकों के लिए संभावित बोलीदाताओं के लिए क्षेत्र दौरों को सुगम बनाना

(ढ) संसद प्रश्न और सूचना का अधिकार

(ण) सीएसओ, डीपीआईआईटी, आईबीएम, आरबीआई, राज्य सरकार और नीति आयोग आदि का समर्थन।

वर्ष 2025–26 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन कार्यालय का निष्पादः

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

1. **कोयला खानों में सीम/सेक्शन को खोलने और फिर से खोलने की अनुमति प्रदान करनाः** वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) में, कोयला नियंत्रक संगठन ने 32 कोयला खानों में सीम/सेक्शन के लिए फिर से खोलने/खोलने की अनुमति दी है।

2. **कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के तहत मामलों का निपटानः** सीसीओ ने वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के तहत कोयला मंत्रालय को 9 मामलों की सिफारिश की है।

3. **ग्रेड स्लिपेज के संबंध में वैधानिक शिकायतः** कोयला नियंत्रक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान 04 मामलों की सुनवाई की है।

4. भारत की कोकिंग कोल क्षमता का विस्तारः वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ग्रेड घोषणा में, कोयला नियंत्रक संगठन ने 44 कोयला सीमों को गैर–कोकिंग कोल से कोकिंग कोल में फिर से वर्गीकृत किया, जो कोयला ग्रेडिंग के इतिहास में इस तरह के पुनः वर्गीकरण की पहली घटना है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मुग्मा क्षेत्र (10 खदानें, 32 सीम) और सालनपुर क्षेत्र (4 खानों, 12 सीम) को कवर करते हुए किया गया यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर, कोकिंग कोल में संसाधन अनुकूलन और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में योगदान देता है।

5. **सीआईएल के अलावा अन्य सभी कोयला और लिग्नाइट कंपनियों के लिए खनन योजना और खानबंद करने की योजना को मंजूरीः** कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना और खानबंद करने की योजना 2025 तैयार करने के दिशानिर्देशों के संबंध में कोयला मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34011/28/2019–सीपीएएम दिनांक 31.01.2025 के अनुसार, सभी खनन योजनाएं कोयला मंत्रालय के एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की टिप्पणियों की आवश्यक संवीक्षा और अनुपालन के बाद, समिति कोयला नियंत्रक को खनन योजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करती है।

   वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) में, 23 खनन योजनाओं और खानबंद करने की योजना को मंजूरी दी गई और 03 को अस्वीकार कर दिया गया।

6. **स्टार रेटिंग नीति के तहत कोयला/लिग्नाइट खानों की समीक्षाः**

   कोयला और लिग्नाइट खानों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, स्टार रेटिंग नीति तैयार की गई है और कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए उसी नीति के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा 01.04.2019 से अनुमोदित किया गया था। स्टार रेटिंग नीति के अनुसार, सात मॉड्यूल में व्यापक रूप से कवर किए गए विभिन्न कारकों के तहत सभी कोयला खानों के कोयला नियंत्रक के संगठन द्वारा स्व–मूल्यांकन और बाद में सत्यापन की एक प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई गई हैः

   क. खनन संचालन संबंधित पैरामीटर

   ख. पर्यावरण संबंधी पैरामीटर

   ग. प्रौद्योगिकियों को अपनानाः सर्वोत्तम खनन प्रथाएं

   घ. आर्थिक निष्पादन

   ङ. पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित पैरामीटर

   च. कार्यकर्ता से संबंधित अनुपालन

   छ. संरक्षा और सुरक्षा संबंधी पैरामीटर

ओपन कास्ट खानों में कुल 50 मूल्यांकन पैरामीटर और भूमिगत खानों में 47 मूल्यांकन पैरामीटर यूजी खानों और ओसी खानों दोनों के लिए स्व–मूल्यांकन के लिए निर्धारित टेम्पलेट्स में इन सात मॉड्यूल में निर्दिष्ट हैं। यूजी और ओसी दोनों प्रचालन वाली मिश्रित खानों के मामले में, खानों की अंतिम रेटिंग की गणना मिश्रित खानके ओसी और यूजी खंडों के कोयला उत्पादन लक्ष्य के भारित औसत पर की जाएगी।

आधार वर्ष 2023–24 के लिए स्टार रेटिंग का निष्पादन इस प्रकार है:

रेटिंग वर्ष	कंपनी का नाम	मूल्यांकन की गई खानों की संख्या	खान का प्रकार	स्टार रेटिंग घोषित खानों की संख्या					
			ओसी. यूजी. मिश्रित	5 स्टार	4 स्टार	3 स्टार	2 स्टार	1 स्टार	कोई स्टार नहीं
2023-24	कुल	383	228+144+11	42	101	137	69	26	8
	बीसीसीएल	31	26+3+2	0	2	14	11	3	1
	सीसीएल	35	32+3+0	2	2	19	8	4	0
	ईसीएल	77	21+49+7	1	7	37	22	10	0
	एमसीएल	19	16+3+0	9	9	1	0	0	0
	एनसीएल	10	10+0+0	6	4	0	0	0	0
	एसईसीएल	61	20+41+0	2	14	23	17	5	0
	डब्ल्यूसीएल	49	31+18+0	4	30	13	2	0	0
	एनईसी	1	1+0+0	0	0	0	1	0	0
	एससीसीएल	38	16+21+1	4	14	20	0	0	0
	एनएलसीआईएल	5	5+0+0	3	2	0	0	0	0
	अन्य	57	50+6+1	11	17	10	8	4	7

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए स्टार रेटिंग प्रक्रियाधीन है। 380 खानों ने स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिया है। 380 प्रतिभागी खानों में से, स्व–मूल्यांकन चिह्नों के सत्यापन के लिए सत्यापन समिति द्वारा उच्चतम स्कोरिंग खानों (43 खानों) के शीर्ष 10% का भौतिक निरीक्षण किया गया है।

क्षेत्रीय क्रॉस–टीम द्वारा शेष 90 प्रतिशत खानों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद मुख्यालय द्वारा अंतिम समीक्षा की जाएगी और परिणाम 20 मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है।

7. कोयला सांख्यिकी का संग्रह, संकलन और प्रकाशनः

सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना एसओ 1682 (ई) दिनांक 8 अप्रैल 2025 के अनुसार, कोयला मंत्रालय के उप महानिदेशक को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और कोयला क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए अधिकृत है।

8. पहले आवंटित कोयला ब्लॉकों के लिए बैंक गारंटी संबंधी मुद्दाः

सीसीओ आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय के निर्देश के अनुसार संबंधित पूर्व आवंटी को रिपोर्ट भेजता है। 34 कोयला ब्लॉक अदालत के मामलों में से:

- 2021–22 में 8 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है
- 2022–23 में 7 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है
- 2023–24 में 5 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है
- 2024–25 में 2 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है
- 2025–26 में कोई बैंक गारंटी वापस नहीं की गई।

9. ब्रिज लिंकेज के माध्यम से लिंकेज कोयले की मात्राः

सीसीओ 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) में स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी) के निर्देशों के अनुसार ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की लिंकेज मात्रा और कोयले के लिंकेज से संबंधित 12 मामलों की मात्रा निर्धारित करता है।

10. खानबंद करने की निगरानी और खानबंद करने की गतिविधि के लिए एस्क्रो खाते का संचालनः

कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खानबंद करने की योजना (प्रगतिशील और अंतिम) के अनुसार खनन

क्षेत्रों की खानबंद करने की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए और खनन योजना और खानबंद करने की योजना तैयार करने के दिशानिर्देशों के संबंध में एमओसी के अनुमोदित खानबंद करने की लागत (ओएम संख्या 34011/28/2019–सीपीआईएम दिनांक 31.01.2025) के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलने के लिए त्रिपक्षीय एस्क्रो समझौते को निष्पादित करने का काम सौंपा गया है। कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक 2025)।

अनुसूचित बैंकों के साथ कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के बीच 46 त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता करार निष्पादित किए गए हैं। कोयला और लिग्नाइट कंपनियों द्वारा एस्क्रो खातों में वार्षिक खानबंद करने की लागत (अनंतिम) के लिए जमा की गई कुल राशि 17626.34 करोड़ रुपये है।

31 दिसंबर 2025 तक, विभिन्न कोयला और लिग्नाइट खानों के एस्क्रो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खानबंद करने की गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति के लिए 3558.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

11. खानों को वैज्ञानिक रूप से बंद करने में ऐतिहासिक उपलब्धिः

आजादी के बाद पहली बार, 15 खानों को अनुमोदित खानबंद करने की योजना के अनुसार वैज्ञानिक रूप से बंद किया गया है। इन खानों के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा अंतिम खानबंद करने के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खदानें सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से बंद थीं।

12. एस्क्रो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खानबंद करने की गतिविधियों के लिए निधि की प्रतिपूर्तिः

वर्ष 2025–26 के लिए, प्रगतिशील/अंतिम खानबंद करने की गतिविधियों के लिए 66 कोयला/लिग्नाइट खानों के लिए प्रतिपूर्ति के लिए 363.26 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

13. समर्पित वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से सामुदायिक विकास और न्यायसंगत परिवर्तन को मजबूत करनाः

सामाजिक रूप से जिम्मेदार और जन–केंद्रित खानबंद करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, संक्रमण के दौरान और बाद में समुदायों का समर्थन करने के लिए स्पष्ट वित्तीय जनादेश पेश किए गए हैं। साथ ही इस आवश्यकता के साथ कि पांच वर्षीय एस्क्रो फंड का 25: सामुदायिक विकास और आजीविका गतिविधियों के लिए समर्पित हो। यह भी अनिवार्य किया गया है कि एस्क्रो फंड का 10 प्रतिशत विशेष रूप से परिवर्तन के लिए निर्धारित किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित समुदायों को कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका सृजन, सामाजिक बुनियादी ढांचे और संक्रमण ाकालीन जरूरतों के लिए संरचित समर्थन प्राप्त हो क्योंकि खनन कार्य समाप्त हो जाते हैं। इन फंडिंग प्रावधानों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य खनन क्षेत्रों में न्यायसंगत, लचीले और भविष्य के लिए तैयार समुदायों को बढ़ावा देना है।

14. हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ खानबंद करने को बढ़ावा देनाः

स्थायी खानबंद करने की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोयला और लिग्नाइट खानमालिकों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए चार हितधारक परामर्श सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन परामर्शों ने जिम्मेदार खानबंद करने, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामुदायिक दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए सहयोगात्मक शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दर्पण–पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और खनन कंपनियों के साथ जुड़ाव की सुविधा प्रदान की। इन जुड़ावों ने प्रभावशाली सामुदायिक विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को पहचानी गई खानों और कंपनियों से जोड़कर साझेदारी का भी समर्थन किया।

15. रिक्लेम फ्रेमवर्कः सामुदायिक जुड़ाव और विकास के लिए प्रैक्टिशनर की पुस्तिकाः

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) ने रिक्लेम फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ खानबंद करने का मार्गदर्शन करने के लिए रीच आउट, एनविजन, को–क्रिएट, स्थानीयकरण, अधिनियम, एकीकृत, रखरखाव के लिए एक संक्षिप्त रूप है। यह ढांचा खानबंद होने के दौरान सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसे पहले ही सात खानों में संचालित किया जा चुका है, अर्थात् धनपुरी ओसी, पिनौरा यूजी, राजनगर ओसीपी, दक्षिण बालंदा ओसी, बसुंधरा पूर्व, दतला ओसी और बरकुही ओसी। बड़े पैमाने पर अपनाने का समर्थन करने के लिए, सीसीओ ने सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल के 200 अधि ाकारियों के लिए प्रशिक्षकों (टीओटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी

आयोजित किए हैं, जो उन्हें अपने संबंधित कार्यों में ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं।

16. संधारणीय खान बन्द करने के लिए लाइव्स फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर की हैंडबुक:

एलआईवीईएस फ्रेमवर्क (भूमि और तकनीकी सुधार, एकीकृत सामुदायिक जुड़ाव और सशक्तिकरण, व्यवहार्य पोस्ट–क्लोजर डेवलपमेंट, इकोसिस्टम पुनर्वास, पुनर्योजी पर्यावरण बहाली और स्थिरता, और प्रबंधन) को खनन भूमि के पुनः उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और लचीले समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए एक संरचित और दूरदर्शी रोडमैप प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह ढांचा 35 खानपुनर्प्रयोजन परियोजनाएं भी प्रदान करता है, जिससे खान मालिकों को स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप सबसे व्यवहार्य पोस्ट–क्लोजर विकल्पों का आकलन करने और अपनाने की अनुमति मिलती है। ढांचे के साथ–साथ, भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक व्यवहार्यता, जलवायु कारकों और सामाजिक–आर्थिक विचारों जैसे प्रमुख इनपुट का विश्लेषण करके उपयुक्त खान पुनर्प्रयोजन परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए एक इंटरैक्टिव निर्णय–समर्थन उपकरण विकसित किया गया है। यह उपकरण हितधारकों को प्रत्येक खनन स्थल की अनूठी विशेषताओं और आवश्यकताओं के लिए परियोजना विकल्पों को तैयार करके सूचित, डेटा–संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे टिकाऊ और प्रभावी पुनर्प्रयोजन समाधानों को बढ़ावा मिलता है।

17. अर्थ फ्रेमवर्क– ड्राइविंग ग्रीन फाइनेंसिंग एंड कार्बन मैनेजमेंट:

कार्बन क्रेडिट अवसरों को रणनीतिक रूप से मैप करने और हरित वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए एआरटीएचए फ्रेमवर्क (संरेखित, रैंक, लक्ष्य, दोहन और अनुकूलन) पेश किया गया है। यह अभिनव ढांचा कार्बन परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन का मार्गदर्शन करके और खनन क्षेत्र में कम कार्बन भविष्य का समर्थन करने वाले निवेश को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ खनन प्रथाओं में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

18. निर्बाध अनुमोदन और बढ़ी हुई पारदर्शिता के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना

एक विकसित भारत और डिजिटल रूप से सशक्त शासन इकोसिस्टम के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, एक सहज और फेसलेस अप्रूवल प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इस डिजिटल सुधार का एक प्रमुख घटक, खनन योजना मॉड्यूल, खनन योजनाओं और खानबंद करने की योजनाओं को ऑनलाइन जमा करने और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है। अपनी स्थापना के बाद से, पोर्टल को 145 खनन योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 133 को संसाधित किया गया है, जिससे औसत प्रसंस्करण समय 4.5 महीने तक कम हो गया है, जबकि पहले की ऑफ़लाइन व्यवस्था के तहत यह 9–12 महीने था।

वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 (आज तक) के दौरान, कोयला नियंत्रक संगठन ने क्रमशः 24 और 23 खनन योजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें औसत प्रसंस्करण समय अंतिम अनुपालन अपलोड करने की तारीख से एक महीने से अधिक नहीं होगा, यानी जब खनन योजना सभी तरह से पूरी हो जाती है, एसडब्ल्यूसीएस पर अपलोड किया गया है।

इन डिजिटल सुधारों के आधार पर, एसडब्ल्यूसीएस पर माइन ओपनिंग परमिशन (एमओपी) मॉड्यूल 7 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। मॉड्यूल पारंपरिक ऑफ़लाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से बदल देता है जो ऑनलाइन सबमिशन, रीयल–टाइम ट्रैकिंग और त्वरित अनुमोदन को सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप, औसत प्रसंस्करण समय 17–2 महीने पहले की तुलना में केवल 3 दिनों तक कम हो गया है। इसके लॉन्च के बाद से, पोर्टल के माध्यम से 32 खानखोलने की अनुमति दी गई है।

19. डायनेमिक डैशबोर्ड के साथ नई आधिकारिक वेबसाइट

सीसीओ ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से माइनिंग प्लान मॉड्यूल और माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल के साथ एकीकृत एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की विशेषता वाली एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह प्लेटफॉर्म स्टार रेटिंग पोर्टल से भी जुड़ता है और इसमें एक डिजिटल सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है, जो एक गतिशील सांख्यिकी डैशबोर्ड के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए वर्गीकृत डेटा प्रदान करती है।

20. भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करें:

कोयला नियंत्रक कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अनुसार अनुसूची–I कोयला खानों के लिए दावों के मामलों को निपटाने के लिए भुगतान आयुक्त के रूप में भी

कार्य करता है। सीओपी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	वितरित राशि
2016-17	₹ 944,69,37,538/-
2017-18	₹ 197,31,98,353/-
2018-19	₹ 2,47,41,088/-
2019-20	शून्य
2020-21	₹ 91,54,13,995/-
2021-22	₹ 36,09,59,649/-
2022-23	₹ 6,11,87,74,048/-
2023-24	₹ 5,53,30,48,350/-
2024-25	₹ 5,09,45,74,374/-
2025-26 (दिसंबर 2025 तक)	₹ 2,61,80,13,399/-

21. वाशरी अस्वीकार के निपटान की अनुमतिः

वित्त वर्ष 2025–26 (16 दिसंबर 2025 तक) के दौरान 33 वाशरियों को 9.37 मिलियन टन वाशरी रिजेक्ट के निपटान की अनुमति जारी की गई थी और 110 आवेदनों पर कार्रवाई की गई थी। यह सीसीटी–13011/3/2007–सीए–I (वॉल्यूम–III), दिनांक 27–05–2021 के माध्यम से मंत्रालय द्वारा जारी वाशरी रिजेक्ट के प्रबंधन और निपटान की नीति के अनुसार है।

22. कोयला खान संरक्षण और विकास खाते से ऋण की राशि का संवितरणः

कोयला नियंत्रक कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम 2021 के तहत गठित कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय सीसीडीएसी के माध्यम से धन जारी करने के लिए कोयला क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्यों, सड़क और रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में कोयला कंपनियों से प्रक्रियाएं प्राप्त करता है और आवेदनों/दावों की जांच करता है । निधि की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष 2025–26 में धन के संवितरण की स्थिति

नोटः चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक सीसीडीए समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा

क्र.सं.	विवरण	जीएन (73.10%)	एनईआर (10%)	टीएसपी (8.60%)	एससी (8.30%)	कुल (करोड़)
1	आवंटित निधि 2025–26 (बीई)	14.62	2.00	1.72	1.66	20.00
2	पिछले वर्ष से अनुमोदित दावा राशि पर खर्च	0	0	2.75	0.92	3.67
3	2025–26 में स्वीकृत दावा राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल राशि (2+3)	0.00	0.00	2.75	0.92	3.67
5	2025–26 (दिसंबर 2025 तक) में वितरण	0.00	0.00	1.72	0.92	2.64

कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)

क्र.सं.	विवरण	जीएन (73.10%)	एनईआर (10%)	टीएसपी (8.60%)	एससी (8.30%)	कुल (करोड़)
1	आवंटित निधि 2025–26 (बीई)	52.63	7.20	6.19	5.98	72.00
2	पिछले वर्ष की स्वीकृत दावा राशि पर खर्च	19.70	0.00	91.16	0.00	110.86
3	2025–26 में स्वीकृत दावा राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल राशि (2+3)	19.70	0.00	91.16	0.00	110.86
5	2025–26 में वितरित (दिसंबर 2025 तक)	19.70	0.00	24.19	0.00	43.89

आज तक की राशि से अधिक

योजना	सामान्य (करोड़)	एनईआर (करोड़)	एसटी (करोड़)	एससी (करोड़)	कुल (करोड़)
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
कोलफील्ड्स में परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास	0.00	0.00	66.97	0.00	66.97

23. आईसीएआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीच 20 नवंबर 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वैज्ञानिक और संधारणीय खानबंद करने और खनन के बाद भूमि बहाली के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है। यह साझेदारी आईसीएआर की कृषि अनुसंधान विशेषज्ञता को सीसीओ के नियामक जनादेश के साथ एकीकृत करना चाहती है, ताकि चुनिंदा पायलट खानबंद करने की परियोजनाओं के साथ शुरुआत की जा सके।

लंबी अवधि में, इस सहयोग से पूरे भारत में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल खानों को बंद करने के लिए एक स्केलेबल ढांचा स्थापित करने, खनन के बाद की भूमि के उत्पादक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने और प्रभावित समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे जिम्मेदार खनन प्रथाओं और समावेशी क्षेत्रीय विकास का समर्थन किया जा सकेगा।

24. कोयला नियंत्रक संगठन को कोल एक्सचेंज के लिए नियामक के रूप में नियुक्त किया गया

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 बी की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने कोयला नियंत्रक संगठन को अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ए में सूचीबद्ध खनिजों के लिए कोयला एक्सचेंजों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए अधिकृत किया है।

नियामक प्राधिकरण के रूप में, सीसीओ कोयला एक्सचेंजों के प्राधिकरण, पंजीकरण और संचालन की देखरेख करेगा, नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देगा और कोयले के संगठित व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।

ये पहल सामूहिक रूप से एक टिकाऊ, तकनीकी रूप से उन्नत और समुदाय–केंद्रित कोयला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक खानों को बंद करने और समावेशी सामुदायिक विकास से लेकर डिजिटल परिवर्तन, कोयले की गुणवत्ता में

वृद्धि और एक पारदर्शी कोयला व्यापार इकोसिस्टम के लिए आधार तैयार करने तक, सीसीओ भारत के कोयला उद्योग में नवाचार, जवाबदेही और लचीलेपन को बढ़ावा देना जारी रखता है, जिम्मेदार खनन और संसाधन प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित करता है।

7. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसे कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान जमा–लिंक्ड बीमा योजना, 1976 और कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के प्रशासन का काम सौंपा गया है। इन योजनाओं को सीएमपीएफओ द्वारा त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड के मार्गदर्शन में प्रशासित किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

31 दिसंबर 2025 तक, सीएमपीएफओ लगभग 3,27,262 भविष्य निधि ग्राहकों और लगभग 4,77,477 पेंशनभोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में स्थित है, जिसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय देश के कोयला उत्पादक राज्यों में कार्यरत हैं।

7.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में, निजी तौर पर संचालित कोक संयंत्रों को छोड़कर, कुल 805 कोयला खानों और कार्यालय इकाइयों को कोयला खान भविष्य निधि योजना के तहत कवर किया गया था। 31.03.2025 तक भविष्य निधि योजना, 1948 की लाइव सदस्यता लगभग 3.32 लाख थी।

वर्ष 2025–26 की अवधि के दौरान (01.04.2025 से 31.12.2025 तक), स्वैच्छिक योगदान सहित भविष्य निधि योगदान लगभग ₹6,220 करोड़ प्राप्त हुए। इसके अलावा, 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान लगभग 1,260 करोड़ रुपये के योगदान की उम्मीद है, जिससे वर्ष के लिए कुल प्रत्याशित योगदान लगभग 7,480 करोड़ रुपये हो जाएगा।

निधि के संपूर्ण संचय को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से निवेश किया जाता है। विशेष जमा योजना (एसडीएस) निवेश और सार्वजनिक खाता होल्डिंग सहित फंड के निवेश का कुल अंकित मूल्य 31.12.2025 तक लगभग ₹1,35,600 करोड़ था। 01.04.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान वृद्धिशील निवेश (अंकित मूल्य) लगभग ₹6,600 करोड़ था, और 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान लगभग ₹500 करोड़ का और निवेश होने की उम्मीद है।

वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान भविष्य निधि से रिफंड, भुगतान किए गए अग्रिमों के साथ, नीचे दिए गए हैं:

	निपटाए गए और वितरित किए गए मामलों की संख्या (01.04.2025 से 31.12.2025) रु	निपटाए जाने और वितरित किए जाने वाले संभावित मामलों की संख्या (01.01.2026 से 31.03.2026) रु
भविष्य निधि वापसी मामले	16983	लगभग 6300
विवाह अग्रिम	1269	लगभग 800
शिक्षा अग्रिम	114 } 2124	
हाउस बिल्डिंग एडवांस	741	
पीएफ रिफंड और अग्रिमों पर वितरित कुल राशि	लगभग ₹10,000 करोड़ (01.04.2025 से 31.12.2025)	लगभग ₹2,900 करोड़ (01.01.2026 से 31.03.2026)

रु सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) योजना के प्रशासन की लागत भविष्य निधि अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के शेयरों) के 3 प्रतिशत की दर से लगाए गए प्रशासनिक प्रभार से पूरी की जाती है, जिसका भुगतान कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को किया जाता है।

7.2 कोयला खान जमा लिंक्ड बीमा योजना

कोयला खान जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, जो कोयला खान भविष्य निधि योजना का सदस्य था, नामिती भविष्य निधि संचय के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान मृतक के खाते में औसत शेष राशि के बराबर अधिकतम ₹10,000 के अधीन राशि प्राप्त करने का हकदार है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ताओं को मूल रूप से कवर किए गए श्रमिकों के कुल वेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से योगदान करना आवश्यक था, और केंद्र सरकार को नियोक्ता के योगदान के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था। वर्तमान में, योजना के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए, नियोक्ता कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से योगदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार कुल वेतन का 0.05 प्रतिशत योगदान करती है, जो नियोक्ता के योगदान का 50 प्रतिशत है।

कोल इंडिया लि (सीआईएल) के कर्मचारियों के कार्यकारी संवर्ग को राजपत्र अधिसूचना सं 201 एस.ओ. 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत योजना के प्रचालन से छूट दी गई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को पहले ही इस योजना के संचालन से छूट दी गई थी।

7.3 कोयला खान पेंशन योजना, 1998

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3ङ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 (ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से छोड़े गए कार्यों को छोड़कर) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 तैयार की। यह योजना 31 मार्च 1998 से लागू हुई।

वर्ष 2025–26 के दौरान, 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान कुल 21,660 नए पेंशन दावों का निपटान किया गया और 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान लगभग 7,200 दावों का निपटान होने की उम्मीद है। 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान योजना के तहत वितरित कुल पेंशन राशि लगभग 4,790 करोड़ रुपये थी, जबकि 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के लिए लगभग 1,700 करोड़ रुपये का वितरण अनुमानित है।

फंड का कोष और इसकी संधारणीयता

पेंशन फंड में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(क) कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की नियत दिन की स्थिति के अनुसार निवल परिसंपत्तियां;

(ख) कर्मचारी के वेतन के दो और एक–तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, कर्मचारी और नियोक्ता के समान शेयरों का कुल योग होने के नाते, नियत दिन से भविष्य निधि से हस्तांतरित किया जाता है;

(ग) 01.04.1989 से कर्मचारी को भुगतान किए गए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दो प्रतिशत के बराबर राशि या शामिल होने की तारीख, जो भी बाद में हो, 31.03.1996 तक, और 01.04.1996 से अनुमानित वेतन का दो प्रतिशत या शामिल होने की तारीख, जो भी बाद में हो;

(घ) एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि, जिसकी गणना 01.07.1995 को वेतन के आधार पर की जाती है या शामिल होने की तारीख, जो भी बाद में हो;

खंड (ख) से (घ) को हटा दिया गया था और खंड (छ) को 01.10.2017 से प्रभावी जीएसआर संख्या 540 (ई) दिनांक 08.06.2018 के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा देय मूल मजदूरी और महंगाई भत्ते के 7 प्रतिशत की दर से योगदान प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था;

(ङ) नियत दिन से केंद्र सरकार द्वारा योगदान किए गए कर्मचारी के वेतन के एक और दो–तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, इस शर्त के अधीन कि जहां वेतन ₹1,600 प्रति माह से अधिक है, केंद्र सरकार का अंशदान ₹1,600 प्रति माह के वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा;

(च) योजना के प्रावधानों के अनुसार नए विकल्प चुनने वालों सहित पेंशन सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि।

वर्ष 2025–26 के दौरान, भविष्य निधि से पेंशन फंड में धन के डायवर्जन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेंशन योगदान एक अलग खाते में जमा किया जाता है। 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान सेवारत सदस्यों का पेंशन योगदान लगभग 4,200 करोड़ रुपये था, और 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए लगभग 1,400 करोड़ रुपये

का योगदान अनुमानित है, जिसमें सरकार का हिस्सा और ब्याज शामिल है।

कवरेज

इस योजना में कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

(क) ऐसे कर्मचारी जो पूर्ववर्ती कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31.03.1998 को रोल पर थे;

(ख) 31.03.1998 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी;

(ग) ऑप्टी सदस्य जिन्होंने फॉर्म पीएस–1 और पीएस–2 में अपने विकल्प का प्रयोग किया, जैसा भी लागू हो, योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन;

(घ) जिन कर्मचारियों की 01.04.1994 से 31.03.1998 तक की अवधि के दौरान सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, जिन्हें जीएसआर संख्या 521 (ई) दिनांक 12.08.2004 के तहत योजना के डीम्ड ऑप्टीज़ के रूप में माना जाता है।

लाभ.

योजना के तहत स्वीकार्य लाभों में शामिल हैं:

(क) मासिक पेंशन (सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या सेवा से बाहर निकलना);

(खॅ) विकलांगता पेंशन;

(ग) मासिक विधवा या विधुर पेंशन;

(घ) बच्चों की पेंशन;

(ङ) अनाथ पेंशन; तथा

(च) अनुग्रह भुगतान।

नोटः वर्ष 2025–26 के लिए कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री में प्रस्तुत सभी आंकड़े 01.04.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए अनंतिम हैं और 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए अनुमानित हैं।